THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) to (c) The continued augmentation of Extra High Voltage lines in the Central Sector and creation/strengthening of the Inter-State and Inter-Regional transmission lines, have provided impetus for evolution of a National Power Grid. The possibility of ultimately having to create a separate organisation at the National level to design, construct, maintain and operate the Extra High Voltage lines for transmission of power from one State/Region to another, cannot be ruled out. The matter, however, requires an in-depth study of all aspects of the problem, including set up of the proposed organisation, Regional grids will form part of such a National Power Grid.

White Paper on Public Sector Undertakings

*148. SHRI PRAMOD MAHAJAN:

SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to lay a white paper on the public sector undertainkgs before Parliament; and

(b) if so, when and what action has so far been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) Yes, Sir.

(b) The White Paper on Public Sector is under finalisation and will be placed before Parliament at the soonest possible.

Unintended Benefits by IDPL and HAL

*149. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the names of bulk drugs being produced by IDPL and HAL which were under price control under DPCO, 1979 and have been exempted from price control under DPCO, 1987;

(b) what was the price of each under DPCO, 1979 present price, percentage increase alongwith production of each during the last three years, year wise;

(c) the names of the drugs for which these companies got foreign technologies, installed plant and machinery and could not succeed in commercial production;

(d) what was the technology cost paid on each, value of plant and machinery installed and what was the production of each during the last three years, year-wise;

(e) whether it is a fact that these companies made crores of rupees as unintended benefit; and

(f) if so, the amount worked out under Para 7(2) of DPCO, 1979?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) Information to the extent available is given in the Annexure in respect of M/s IDPL [*See* Appendix CXLVIII, Annexure No. 53]. All the bulk drugs produced by M/s. HAL which were under price control of DPCO, 1979 continue to be under the price control of DPCO, 1987.

(c) To the extent information is available, no foreign technologies employed by these companies resulted

in unsuccessful commercial production in respect of price de-controlled drugs.

(d) Does not arise.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

गांवों में डॉक तथा टेली-संचार सुविधायें

*150. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :**
श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गांवों की संख्या क्या है जिनकी आबादी 1500 है और जिनमें पिछले तीन वर्षों में डाक तथा टेली-संचार सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं ;

(ख) इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में सांगली में ये सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) :

(क) (1) डाक

(1) ग्रामीण सेक्टर में, उन ग्राम समूहों में नए डाकघर खोले जाते हैं जिनकी संयुक्त जनसंख्या सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 और पहाड़ी, पिछड़े तथा जन जातीय क्षेत्रों में 1500 हो । 1-4-85 से 31-3-1988 की अवधि के दौरान, सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 338 और पहाड़ी पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 536 नए डाकघर खोले गए ।

(2) दूरसंचार

विभाग द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता क्यों कि दूरसंचार सुविधाएं इस मानदण्ड के आधार पर प्रदान नहीं की जाती हैं । दीर्घकालिक उद्देश्य के रूप में, विभाग ने प्रत्येक आबादी वाले स्थान के लगभग 5 कि०मी० के भीतर पूरी आर्थिक सहायता देकर दूरसंचार सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है । इसके लिए, देश को 5 कि०मी० के षटभुजाकार वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तथा इसके प्रमुख ग्राम को दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है । देश में ऐसे 50421 षटभुजाकार वाले क्षेत्र हैं जिनमें से 28,447 क्षेत्रों में 31-3-1988 तक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं ।

(ख) (1) डाक

ब्योरा विवरण-I में दिया गया है (नीचे देखिये)

(2) दूरसंचार

ब्योरा विवरण II में दिया गया है (नीचे देखिये).

(ग) (1) डाक

जी हां । सागली जिले में इस समय 313 ग्रामीण डाकघर काम कर रहे हैं । चालू वर्ष के दौरान 5 और ग्रामों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(2) दूरसंचार

सांगली (महाराष्ट्र) में निम्नलिखित दूरसंचार सुविधाएं हैं :

1. 4800 लाइनों की क्षमता वाला स्ट्रोजर आटोमेटिक एक्सचेंज ।

2. सांगली एक्सचेंज राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग पर बंबई टी ए एक्स से जुड़ा हुआ है ।